प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

बल सभी पर विजय प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह जीत अल्पकालिक है।
-अब्राहम लिंकन

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

गढ़चिरौली में हुआ हमला बताता है कि माओवादी अपने कथित 'एमएमसी जोन' में गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, लिहाजा इस क्षेत्र के तीन राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने की जरूरत है।

एक और नक्सली हमला

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के एक दल पर बारूदी विस्फोट के जरिये हमला कर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी का एक बार फिर एहसास कराया है। इस हमले में महाराष्ट्र पुलिस के त्वरित कार्रवाई बल के 15 जवान और उनके वाहन के ड्राइवर की मौत हो गई। गढ़चिरौली में एक दशक के बाद सुरक्षा बलों पर यह सबसे बड़ा हमला है। इस हमले ने फिर दिखाया है कि सुरक्षा बल माओवादी प्रभावित इलाकों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) को अपनाने में कहीं न कहीं चूक कर जाते हैं। हालांकि महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख ने आईईडी विस्फोट के जरिये किए गए इस हमले में किसी तरह की खुफिया चूक से इनकार किया है। मगर इस हमले से कुछ घंटे पहले ही नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सटे गढ़चिरौली के कुरखेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क निर्माण में लगी एक निजी कंपनी के तीस से अधिक वाहनों को फूंक दिया था। ये जवान इस घटना की जानकारी के बाद ही वहां के लिए रवाना हुए थे और फिर घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट का निशाना बन गए। यह सूचना थी कि नक्सली पिछले वर्ष 22 अप्रैल को गढ़चिरौली में पुलिस मुठभेड़ में हुई अपने चालीस साथियों की मौत की बरसी मना रहे हैं, लिहाजा यहां अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत थी। माओवादियों ने यह हमला ऐसे समय किया है, जब राज्य में लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में ही दर्ज किया गया। माओवादी किसी भी तरह से निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, जिससे वे अपनी ओर ध्यान खींच सकें। इससे पहले नौ अप्रैल को माओवादियों के हमले में दंतेवाड़ा के विधायक और सुरक्षा बलों के चार जवानों की मौत हो गई थी। गढ़चिरौली के हमले ने माओवादियों की रणनीति में आए बदलाव की ओर भी इशारा किया है, जिस पर गौर करने की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि बस्तर में सुरक्षा बलों का दबाव पड़ने के कारण माओवादी अपने कथित 'एमएमसी जोन' यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों को जोड़ने वाले जंगलों से घिरे गलियारे में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। जाहिर है, माओवादियों से निपटने के लिए इन तीनों राज्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत है।

काम आई हमारी कूटनीति

मसूद अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित हो जाने भर से हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब पाकिस्तान पर दबाव डालने की जरूरत है कि वह उसे अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को सौंपे या फिर भारत के हवाले करे।

मारुफ रजा, सामरिक विश्लेषक

दुनिया के शक्तिशाली देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन पर बहुत दबाव डाला, जिसका नतीजा है कि चीन ने अपना रवैया बदला और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। हालांकि फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा था कि चीन या जो भी देश मसूद को वैश्विक आतंकी मानने के खिलाफ हैं, वे इसकी वजह दुनिया के सामने रखें। इन दबावों की वजह से चीन थोड़ा दब गया। जबकि अब तक चीन का मानना था कि भारत जिस तरह दलाई लामा को अपने यहां शरण देता है, उसी तरह पाकिस्तान भी मसूद अजहर को अपने यहां रखकर कोई गलत काम नहीं कर रहा। पर सबको यह पता है कि दलाई लामा एक नेक व्यक्ति हैं, जबकि मसूद अजहर आतंकवादी है।

चीन चूंकि अपनी आर्थिक ताकत की वजह से दुनिया में मजबूत हो गया है, इसलिए हर जगह वह अपना कानून लागू करने की कोशिश करता है। लेकिन दबाव के सामने उसके झुक जाने से साबित हो गया है कि चीन से अगर आप टक्कर लेने की कोशिश करें और हिम्मत करके खड़े रहें, तो वह धीरे-धीरे पीछे हट जाता है, जैसे दोकलम के मसले पर हुआ था। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के अन्य देशों का भारत के साथ खड़े होने का कारण यह भी है कि हमने इस मुद्दे पर हौसला दिखाया और बालाकोट में हवाई हमले जैसी कार्रवाई की।

मसूद अजहर के मसले पर भारत की इस कामयाब कोशिश के पीछे पिछले तीन-चार साल में कूटनीतिक स्तर पर मोदी सरकार की पहल रही है। इससे पाक प्रायोजित आतंकवाद को लेकर दुनिया के ताकतवर देशों की राय बदली है। इस मामले में भारत इसलिए भी फायदे में रहा, क्योंकि ये सभी देश पाकिस्तान की हरकतों से थक चुके हैं। इनमें अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा भी है कि 'पाकिस्तान हमारे साथ धोखा करता आया है, इसी धोखे में उसने हमसे 30 से 35 अरब डॉलर खाए हैं। इसकी हरकतों पर हम भरोसा नहीं कर सकते।' अमेरिका ने ही बाकी देशों पर भी दबाव डाला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें पांच स्थायी देश हैं, जबकि दस अस्थायी। अभी जो सदस्य देश हैं, उनके साथ अमेरिका ने अंदरखाने कूटनीतिक पहल की होगी, जिससे 14 देश मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के पक्ष में खड़े हो गए।

चीन पर यह दबाव पड़ा कि अब आप यह साबित कीजिए कि किन कारणों से आप मसूद को आतंकवादी नहीं मानते। ऐसे में चूंकि उसे दुनिया के सामने नीचा होना पड़ता, इस कारण वह हिल गया। इसके अलावा भारत की कूटनीतिक पहल भी मजबूत थी। विदेश सचिव विजय गोखले हाल ही में बीजिंग गए थे। उनकी वह यात्रा दुनिया को यह दिखाने की कोशिश थी कि हम मसूद के मसले पर चीन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रालय को यह विश्वास हो गया था कि इस बार चीन इस मसले पर रुकावट नहीं डालेगा। चीन के पास हालांकि वीटो करने का एक और मौका था। लेकिन उसने आंतरिक स्तर पर मूल्यांकन किया होगा कि दोकलम व कुछ अन्य मुद्दों पर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच जो खाई पैदा हुई, उसे पाटने का यह एक मौका है।

हलांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सूची में पुलवामा हमले व कश्मीर में जैश प्रायोजित आतंकवाद को शामिल नहीं किया गया। हमें समझना होगा कि किसी एक मामले के लिए किसी को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर का मामला 2009 से था। उसने हमारी संसद पर हमला करवाया, पठानकोट और अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमले करवाए। बीच में उससे पाकिस्तान ने किनारा कर लिया था, पर दोनों में कुछ समझौता हुआ। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने का प्रतीकात्मक मतलब ही है और इससे कुछ खास हासिल नहीं होने वाला।

यह कदम प्रतीकात्मक जरूर है, पर इस मामले को यहां से आगे बढ़ाना अब आने वाली सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद भी मसूद अजहर लंबे समय तक रावलपिंडी स्थित सैनिक अस्पताल में रहा, तो अब भारत को दुनिया को यह दिखाना होगा कि जिसे वैश्विक आतंकी घोषित किया गया, वह तो पाक सेना की गोद में खेल रहा है। पाक सेना के प्रवक्ता जनरल गफूर ने कहा है कि उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं। पर जो बड़े आतंकवादी समूह हैं, उन्हें अभी तक न तो प्रतिबंधित किया गया और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उनसे लड़ने से पाक सेना अब डरती है, क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार और आत्मघाती आतंकी हैं, जो उनका जीना हराम कर देंगे। ऐसे में अब भारत को विश्व बिरादरी से पाकिस्तान पर अंकुश लगाने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि यह साबित हो गया है कि मसूद पाक सेना के संरक्षण में है।

पहला काम तो यह होना चाहिए कि पाक सेनाधिकारियों के परिजनों को अमेरिकी वीजा न मिले, क्योंकि अधिकतर सेनाधिकारियों के बच्चे वहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए जब तक वह आतंकियों को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाकर अंतरराष्ट्रीय अपराध कानून के तहत सजा न दिलवाए, तब तक उसे आईएमएफ से कर्ज नहीं मिलेगा।

चीन को भी यह समझाने की जरूरत है कि वह भले संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो, पर अगर वह पाकिस्तान का इसी तरह सहयोग करता रहा, तो भारत में उसके सभी निवेशों को रोक दिया जाएगा और चीन से आयातित वस्तुओं पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही, भारत-पाक या कश्मीर मसले पर चीन दखल देगा, तो भारत चीन से रूठे देशों को रक्षा तकनीक उपलब्ध कराने में देर नहीं करेगा। भारत को चीन के खिलाफ माहौल बनाने की जरूरत है।

मसूद अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित हो जाने भर से आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमें दुनिया के देशों को बताना होगा कि संयुक्त रूप से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि या तो वह मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल सौंपे या फिर भारत के हवाले करे, ताकि उसे सजा दी जा सके।

अंतर्ध्वनि

>> कृष्णबिहारी मिश्र

पुराने मकान का छंद आंगन और ओसारे से समृद्ध होता था

मेरे ग्रामांचल में इधर निर्माण-कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। जिस तेज रफ्तार से मेरे ग्रामांचल की रुचि बदल रही है, लगता है नीम-पाकड़ को काटकर हर दरवाजे पर अब जूही-कामिनी रोपी जाएगी, बबूल-बांस को वन में खेद दिया जाएगा। नागर रुचि की गिरफ्त में उलझते, गंवई आदमी में प्रकृति-परिसर के प्रति अरुचि बढ़ती जाएगी। अपने नफीस घरों की हिफाजत में लोग अपने-अपने घरों में सिमट जाएंगे। बिजली की सुविधा चौपाल-अलाव की सामाजिकता को मार देगी, अपने-अपने टीवी सेट से लोग बंध जाएंगे। लोगों की प्रखर स्पर्धा के दो ही बिंदु हैं-दहेज और मकान। मकान के लिए दहेज का स्तर ऊंचा हो रहा है, और दहेज का भाव बढ़ाने के लिए नई डिजाइन के मकान उठ रहे हैं। नागर तहजीब से उसे अलंकृत किया जा रहा है। संतति को शहरी मुहावरे बलात रटाए जा रहे हैं ताकि सभ्यता की दौड़ में वह पिछड़ न जाए। ग्राम्य सहजता की धुरी को क्षत करने का कारोबार बड़े जोर से चल रहा है। भौतिक वैभव अर्जित करने की व्याकुल स्पृहा बड़ों को इतना भी विचार नहीं करने देती कि बच्चों की रुचि और निजी क्षमता क्या है! पॉलीटेकनिक स्कूल में भर्ती होने और पुलिस की नौकरी पाने पर समान उल्लास से गाजे-बाजे के साथ देवता पूजे जाते हैं, कीर्तन-अनुष्ठान आयोजित होते हैं। गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, उच्चतर विद्यालय और महाविद्यालय खुल रहे हैं। भोजपुरी किसान भी अपने घर के दूल्हे को अंग्रेजी पोशाक से सज्जित करना जरूरी मानने लगा है। नागर शिल्पवाले मकान में आंगन सिकुड़ गया है और लंबे ओसारे को खुशनुमा ड्रॉइंग रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। नए उठनेवाले मकान का शिल्प अशुभ संकेत दे रहा है। पुराने मकान का छंद आंगन और ओसारे से समृद्ध होता था। अब 'ड्रॉइंग रूम' का कपाट खास के लिए खुलता है।

-चर्चित लेखक।

मंजिलें और भी हैं

>> एलिजाबेथ याम्बेन

लंदन की नौकरी छोड़ हर्बल टी बेचती हूं

मैं मणिपुर की राजधानी इंफाल में पैदा हुई। चूंकि मणिपुर समेत पूर्वोत्तर में उग्रवादी गतिविधियां हमेशा होती रहती हैं, इसलिए मेरे पिता ने पढ़ाई के लिए मुझे लंदन भेज दिया। वहां अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट की नौकरी करने लगी। लेकिन थोड़े समय के बाद मोटा वेतन और ऐश-ओ-आराम की जिंदगी मुझे खलने लगी थी। मैं बारह साल की उम्र में इंफाल से निकल गई थी। लेकिन लंदन में रहते हुए मुझे बार-बार इंफाल की याद आती थी। लंदन की तुलना में इंफाल मुझे अचानक ज्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वहां की प्रकृति साफ थी और विविध प्रकार की वनस्पतियां वहां थीं। बचपन में कोई भी घर में बीमार पड़ता था, तो दादी दवा के बदले किन्हीं खास पौधों के पत्ते उबालकर या उनका रस निकालकर पिलाती थी, तो वह स्वस्थ हो जाता था। मणिपुर दो चीजों के कारण प्रसिद्ध है-फुटबॉल और चाय। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि स्थानीय वनस्पतियों की अगर ढंग से मार्केटिंग की जाए, तो इसका बहुत लाभ होगा। लेकिन मेरे माता-पिता मेरे आइडिया से खुश नहीं थे। उनको डर था कि लंदन की बनी-बनाई नौकरी छोड़कर मणिपुर लौटना बहुत गलत फैसला होगा। इसी बीच मेरा तबादला सिंगापुर हो गया। वहां मेरा मन और भी नहीं लगा और कुछ महीने नौकरी करने के बाद मैं इंफाल लौट आई।

मुझे खुशी है कि अपने लोगों के लिए काम कर रही हूं। इससे स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार मिला है।

घर लौटकर कुछ महीने तक मैंने मणिपुर की विशेषता के बारे में जानकारी इकट्ठा की। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं स्थानीय औषधियों की बेहतरीन मार्केटिंग करूंगी। इसी के तहत मैंने इंफाल शहर के चर्चित मदर'स मार्केट में, जहां सिर्फ महिलाएं ही दुकान चलाती हैं, ड्वेलर टी नाम से एक दुकान खोली। यहां अलग-अलग औषधियों और फलों का रस मिलाकर चाय तैयार की जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। इसके अलावा जड़ी-बूटी युक्त चाय पैकेटों में बाहर भी भेजी जाती है। दुकान में नौ और महिलाएं मेरे साथ सुबह से रात तक काम करती हैं। लेकिन मेरे इस स्टार्ट अप से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। मैं महिलाओं को कुछ खास वनस्पति अपने खेतों में उगाने के लिए कहती हूं, फिर उसे उनसे खरीद लेती हूं। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अनेक तरह के फल, जो यों ही पड़े रहते हैं, मैं किसानों से खरीद लेती हूं। और फिर इनका अपनी हर्बल टी में इस्तेमाल करती हूं।

बाजार में जड़ी-बूटी बेचने आने वालों से भी मैं जड़ी-बूटियां खरीदती हूं। मणिपुर में भारतीय जैतून और लैमनग्रास का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन इनकी मांग नहीं है। जबकि ये औषधीय गुणों से भरपूर हैं। लिहाजा मैं इन्हें खरीदती हूं और चाय में इस्तेमाल करती हूं। औषधीय वनस्पतियों और फलों के अलावा मैं कुछ सब्जियों का रस निकालकर भी चाय में इस्तेमाल करती हूं। मेरी चाय की मांग पूरे देश में है। पिछले साल से मैंने पैकेटबंद हर्बल टी की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। जल्दी ही मैं इंफाल शहर में ऐसी चार और दुकानें खोलूंगी, क्योंकि इस चाय की भारी मांग है। मुझे खुशी है कि मणिपुर लौटकर मैं अपने लोगों की सेवा कर पा रही हूं। मेरे माता-पिता भी बहुत खुश हैं और वे इस काम में मेरी पूरी मदद करते हैं।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

आचार संहिता की वैधानिकता

सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिलने मात्र से इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता। कोई दल या प्रत्याशी आचार संहिता को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। इसी कारण पार्टी और प्रत्याशी धड़ल्ले से इसका उल्लंघन करते हैं।

राजेश बादल

भारतीय लोकतंत्र में सत्रहवीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव अनेक गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस चुनाव में प्रचार के दरम्यान घटिया और शर्मनाक तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। निर्वाचन आयोग किसी को अड़तालीस घंटे के लिए प्रचार से रोक देता है, तो किसी को बहत्तर घंटे के लिए। किसी को रेड कार्ड दिखा कर नजरबंद कर देता है, तो किसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर देता है। इससे अधिक कार्रवाई करने की इच्छा आयोग के वर्तमान सदस्यों में नहीं दिखाई देती। टी एन शेषन का जमाना शायद ही कभी लौटेगा।

सवाल यह है कि चुनाव दर चुनाव प्रचार के दौरान दरक रहे संयम के इस बांध को टूटने से कैसे रोका जाए? चुनाव आयोग से जब सर्वोच्च न्यायालय जवाब-तलब करता है, तो आयोग अपनी बेचारगी का रोना रोता है। जब अदालत फटकार लगाती है, तो दो चार दिन कड़क नजर आता है। ताज्जुब होता है कि क्या इसी चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को 1977 में बाहर का दरवाजा दिखाया था और क्या यह वही चुनाव आयोग है, जिसने पीवी नरसिंह राव की सरकार को दिन में तारे दिखा दिए थे?

खुद नेहरू सरकार ने महसूस किया था कि किसी भी निर्वाचित सरकार को अगले चुनाव में सरकारी संसाधनों का प्रचार के लिए उपयोग करने का नैतिक अधिकार नहीं है। वैसे तो पहले आम चुनाव में ऑल इंडियो रेडियो पर कांग्रेस समेत किसी भी दल को अपने प्रचार की खबरें या सूचनाएं प्रसारित करने की इजाजत नहीं थी। उस चुनाव में केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रेडियो पर प्रचार की सुविधा पाई थी। यह सुविधा उसे सोवियत संघ के मॉस्को रेडियो ने दी थी। जब दो चुनाव हो गए और राजनीतिक दलों के बीच कड़वाहट पनपने लगी, तो जवाहर लाल नेहरू की पहल पर 1960 में सभी पार्टियों ने मिलकर एक आदर्श आचार संहिता को अंतिम रूप दिया। केरल के विधानसभा चुनाव में इसे पहली बार अमल में लाया गया। जब 1962 के लोकसभा चुनाव आए, तो आयोग ने इस आचार संहिता को परिष्कृत रूप में सभी दलों को वितरित किया। लोकसभा और विधानसभाओं के 1967 में चुनाव हुए, तो एक तरह से पहली बार यह आचार संहिता अमल में लाई गई। जब 1979 में मध्यावधि चुनाव हुए, तो राजनीतिक माहौल बदला हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त एस एल शकधर की अगुआई में चुनाव आयोग ने मजबूती दिखाई और सभी दलों से बात कर संहिता में एक नया हिस्सा जोड़ा। इसमें सत्तारूढ़ दल पर कुछ नई बंदिशें लगाईं गईं। मकसद यही था कि सरकार चला रही पार्टी को अन्य दलों की अपेक्षा शक्तियों के अधिक इस्तेमाल का अवसर न मिले। टी एन शेषन के कार्यकाल में आचार संहिता को और सख्त बनाया गया। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि किसी की निजी जिंदगी पर हमला नहीं किया जाएगा, सांप्रदायिक आधार पर भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील नहीं होगी। सरकारी कार्यक्रमों, नई नीतियों और फैसलों के एलान पर रोक लगाईं गई। प्रधानमंत्री- मंत्रियों के दौरे में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के दिशा-निर्देश भी बनाए गए।

विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिलने मात्र से इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता। अगर कोई दल या उम्मीदवार संहिता तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। इसी कारण पार्टी और प्रत्याशी धड़ल्ले से आचार संहिता तोड़ते रहे हैं। बेशक निर्वाचन का मामला अदालत में जाने से देरी होगी, मगर जब सभी पार्टियां इसे कानूनी रूप देने पर राजी हो जाएंगी, तो फिर इस तरह का प्रावधान भी जरूरी हो जाएगा कि ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर करके प्रकरण का निराकरण करें।

खुली खिड़की

विश्व में गरीबी का हाल

तमाम योजनाओं व कार्यक्रमों के बावजूद गरीबी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के विभिन्न देशों में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोग मौजूद हैं। सबसे ज्यादा गरीब नाइजीरिया में मौजूद हैं।

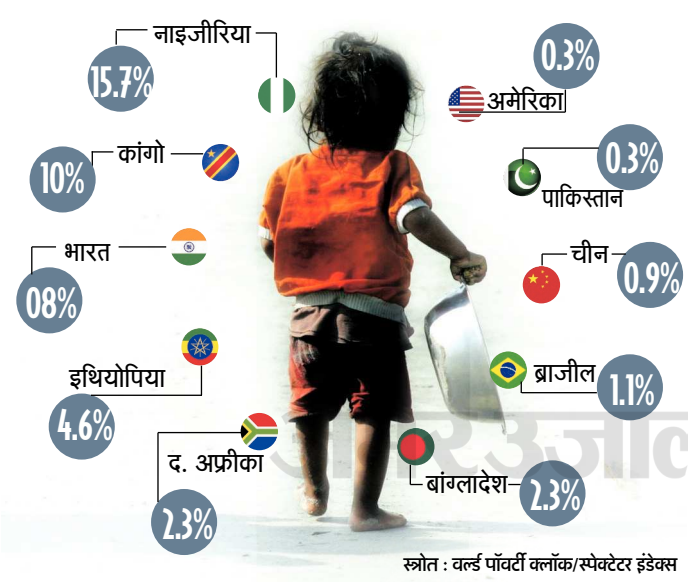

स्रोत : वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक/स्पेक्टेटर इंडेक्स

ईसा की सीख

सत्संग

महात्मा ईसा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें अपना शिष्य मैथ्यू दिखाई पड़ा। मैथ्यू के पिता की मृत्यु हो गई थी और वह उसे रो-रोकर दफन कर रहा था। मैथ्यू ने जैसे ही ईसा को देखा, वैसे ही दौड़कर उनके पास आ गया और ईसा की आस्तीन चूमकर तुरंत दौड़ते हुए पिता के शव के पास चला गया। ईसा ने मैथ्यू को अपने पास बुलाया और कहने लगा, जिसकी मृत्यु हो गई, वह भूत का साथी हुआ। तू उसकी लाश से मोह कर वर्तमान से दूर होना क्यों चाहता है? जब तक मैथ्यू कुछ समझता, ईसा बोल पड़े, समय बड़ा बलवान है। इसने अनेक लाशों को यत्नपूर्वक दफना दिया है। उसके लिए तेरे पिता की लाश दफनाना कोई कठिन काम नहीं है।

वे आगे चले, तो ईसा को अपना एक और शिष्य दिखा। संयोग से वह भी अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था। वह ईसा को देखते हुए उनके पास चला आया और उनके साथ-साथ चलने लगा। ईसा ने थोड़ी देर उससे बातें कीं, फिर कहा, जाओ, पिता का अंतिम संस्कार करके फिर मेरे पास आना। मैथ्यू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ईसा से पूछा, आपने मुझे तो पिता का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, लेकिन इसे जाने दिया। ऐसा क्यों? ईसा बोले, तुम अभी तक मोह में पड़े थे, इसलिए तुम्हें बताना पड़ा। लेकिन मेरा दूसरा शिष्य मोह में नहीं पड़ा है। जो मोह-माया से मुक्त है, उसे क्या सिखाना।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

रीमा, राहुल और मदद

रीमा की कहानी, जिसकी सोच एक अनजान युवा राहुल ने बदल दी।

रात का समय था और सड़क सूनसान। डर के मारे रीमा की हालत खराब थी। गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। वह गाड़ी से निकल कर बाहर खड़ी हो गई, ताकि किसी से मदद मांग सके। दूर से उसे एक मोटरसाइकिल आती दिखी। मोटरसाइकिल वाला खुद ही रुक गया। उसने रीमा से कहा, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आप चिंता न कीजिए। गाड़ी में बैठिए, मैं टायर बदल देता हूं। रीमा गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में राहुल ने टायर बदल दिया। रीमा बोली, बताइए, मैं आपको कितने पैसे दे दं। राहुल ने कहा, मैंने यह काम पैसों के लिए नहीं, आपकी मदद के लिए किया है। जब मैं कभी मुसीबत में था, तब मेरी भी किसी ने मदद की थी। आप भी अगर किसी जरूरतमंद को देखें, तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। रीमा भी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप के पास रीमा को एक छोटी-सी चाय की दुकान दिखी। वह चाय पीने उतरी, तो देखा कि पच्चीस-छब्बीस साल की एक युवती दुकान संभाल रही थी। वह गर्भवती थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। रीमा ने उसे सौ रुपये का नोट दिया, और जब तक वह उसके छुट्टे वापस लाती, रीमा वहां से चली गई। उस युवती ने देखा, कागज के एक टुकड़े पर रीमा कुछ लिखकर पांच सौ रुपये के चार और नोट छोड़ गई थी। उस पर लिखा था, जब मैं मुसीबत में थी, तब मेरी भी किसी ने मदद की थी। यह मेरी मदद समझना। वह लड़की जानती थी किस तरह उसका पति दिन-रात काम करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए पैसे जमा कर रहा था। वह जब दुकान से घर लौटी तो देखा कि उसका पति राहुल सो रहा था। उसने उसके कानों में धीरे से कहा, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता।

हम जैसा बर्ताव दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी होगा।